के लिए विशेष प्रयत्न किए जाने हैं और अप्रैल में अकातोज के अवसर पर ये कार्यक्रम चरण सीमा पर होंगे।

5. बालिकाओं के प्रति भेदभाव पूर्ण व्यवहार को स्वीकारते हुए राष्ट्रीय विकास योजना में विशेष व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बालिकाओं की स्थिति पर नजर रखी जा सके।

6. 18 वर्ष की आयु तक लड़कियों की शादी टालने के लिए लड़कियों और उनके परिवार को प्रोत्साहन देने हेतु प्रारम्भ में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान ये 4 राज्यों में किशोरी विकास केन्द्रों की स्थापना करना।

7. निर्धन शहरी बालिकाओं की समस्या के समाधान के लिए नवीन योजनायें समस्या विशेष हों और प्रायोगिक परियोजनाएं हों ताकि उनमें फेरबदल हो सके।

अखिल भारतीय आंगन बाडी कर्मचारी संघ की मांगें

*1064. **सरदार जगजीत सिंह अरोडा** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने हाल ही में अपनी मांगों के समर्थन में सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो इन कर्मचारियों की मांगें क्या हैं,

(ग) क्या सरकार ने इन कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है और उनकी मांगों के संबंध में उनसे बातचीत की है; और

(घ) यदि हां, तो यह बातचीत कब हुई थी तथा उसका क्या परिणाम रहा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उप मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ और अखिल भारतीय कामगार संघ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारियों के बराबर का दर्जा दिए जाने और सरकारी कर्मचारियों को स्वीकार्य नियमित वेतनमान और अन्य सुविधाएं दिए जाने की मांग को लेकर सरकार को एक ज्ञापन दिया है।

(ग) और (घ) इन दोनों महासंघों के प्रतिनिधि इस विभाग के अधिकारियों से मिले थे। उन्हें यह स्पष्ट किया गया कि समेकित बाल विकास सेवा योजना (आई०सी०डी०एस०) की धारणा ग्रामीण स्तर पर स्वयंसेवी सेवाओं तथा सामुदायिक सहभागिता सिद्धान्तों पर आधारित है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं अंशकालिक, अवैतनिक और स्वयंसेवी कार्यकर्ता होती हैं। उन्हें सरकारी कर्मचारियों के समान नियमित वेतनमान और भत्ते दिया जाना सामुदायिक-सहभागिता की धारणा के विपरीत है। उनसे प्रतिदिन लगभग साढ़े चार घंटे कार्य करने की ही अपेक्षा की जाती है। मांग की भारी वित्तीय कठिनाइयों और इसके व्यापक प्रभावों के अलावा, इन्हीं कारणों से इन कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा देना सरकार के लिए संभव नहीं होगा।

Use of cassettes as better baby sitters

**1065. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of WELFARE be pleased to state;

(a) whether Government's attention has been drawn to a report which appeared in the Economic Times dated the 26th April, 1989 under the caption "Times for Tiny Tots";

(b) if so, whether there is any proposal under Government's consideration to encourage the use of cassettes as better baby sitters; and

(c) if so, what are the details in this regard?

*पूर्वत अतारांकित प्रश्न 771, 15 मई, 1990 से स्थानान्तरित।

**Previously Unstarred Question 802, transferred from the 15th May, 1990.